IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

"रीवा जिले में जल संसाधन एवं भौगोलिक अध्ययन"

(हुजूर तहसील के विशेष संदर्भ में)

डॉ. ध्रुव कुमार द्विवेदी[1] एवं हेमन्त कुमार उद्धे[2]

प्राचार्य, सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोधार्थी, शोध केन्द्र– भूगोल विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांशः रीवा जिले के हुजूर तहसीलनगर भारत के मानचित्रों में 24 डिग्री 32 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 81 डिग्री 24 अंश पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इस नगर की ऊँचाई समुद्र तल से 1045 फिट है। रीवा जिले के हुजूर तहसीलनगर प्राकृतिक सम्प्रदाओं में बहुत ही सम्पन्न है। हुजूर तहसील मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी में स्थित छोटा सा नगर है। रीवा नगर को सफेद शेर की धरती भी कहा गया है। रीवा के उत्तर से इलाहाबाद दक्षिण से कटनी पूर्व से सीधी एवं पश्चिम में सतना जिले से घिरा हुआ नगर है।

प्रस्तावनाः

किसी विषय का गहन व सूक्ष्म अध्ययन करके विषय के संबंध में कुछ नवीन तथ्यों की खोज करना शोध कहलाता है। अंग्रेजी में शोध को रिसर्च कहाँ जाता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। Re + Search जिसमें Re का अर्थ पुनः और दूसरे शब्दों में अर्थात् Search का अर्थ है खोज करना। अतः शोध का अर्थ गहन तथा पुनः अध्ययन करने के उपरान्त नवीन तथ्यों की खोज करना है। यह एक प्रकार से सावधानी पूर्वक किया गया अन्वेषण या जाँच–पड़ताल है। शोध के शोध की योजना विधि को निम्न लिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। हुजूर तहसील में जल संसाधन के विकास से गांव में निवास करने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति में अन्तर आया है। वह अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उनका जीवन स्तर में कुछ सुधार हो रहा है। वे अपनी अवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं। वे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। मेरा उद्देश्य शासन का ध्यान उनकी समस्याओं और उनकी आर्थिक स्थिति की ओर आकृष्ट करना ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके और शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त है।

किसी कार्य को करना पूर्णता इस बात पर निर्भर करता है कि जल संसाधन के विकास (नहर, कुंआ, तालाब) के कार्य के सम्पादन से पूर्ण उसके प्रारंभ करने और उसके सम्पादन के उपायों के संबंध में कई प्रकार की कल्पना कर ली और उसके सम्पादन की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली जाये। इस शोध–कार्य का प्रमुख बिन्दु हुजूर तहसील जिला–रीवा में जल संसाधन से लाभान्वित होने वाले परिवारों की आर्थिक स्थित पर प्रकाश डालना है। वर्तमान शोध–पत्र में हम यह परिकल्पना मानते हैं कि एक ओर वही देश तीव्र गति से विकास कर रहा है। वहीं दूसरी ओर गरीबी निरंतर बढ़ती जा रही है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हुजूर तहसील के अन्तर्गत जल संसाधन के क्षेत्र में निवासरत कृषि के जरिये उन्हें मूल–भूत सुविधायें उपलब्ध कराता हैं।

एक बड़ी जनसंख्या का भाग निर्धन है और गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। वे आज भी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े है। यद्यपि शासकीय योजना इसके लिए बनाई गई है, पर इन्हें लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है ? प्रस्तुत शोध–पत्र इसी परिकल्पना पर आधारित है। तथा शोधार्थी इस वर्ग का

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

समंकों निदर्शन साक्षात्कार व अनुसूची के माध्यम से जानने का प्रयास किया है कि इस वर्ग के समाज की मुख्यधारा से कैसे किया जाए ताकि ये भी समाज में मूलभूत सुविधायें उठा सके और जीवन स्तर ठीक कर सके। शोध क्षेत्र का अर्थ है कि कार्य का प्रमुख क्षेत्र हुजूर तहसील जिला–रीवा में जल संसाधन के क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों में निवास करने वाले परिवारों की जल संसाधन पर आधारित विकास का अध्ययन करना है तथा उनकी समस्याओं को प्रकाश में लाने का प्रयास करना है।

साक्षात्कार से तात्पर्य आमने–सामने बैठकर चर्चा करता है। मैंने सर्वक्षण साक्षात्कार का कार्य साथ–साथ किया करैहिया एवं सगरा में निवास करने वाले गांवों में जाकर उनसे साक्षात्कार करने का निश्चिय किया और जल संसाधन पर आधारित आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और जल के द्वारा उत्पन्न खेती किसानी को समझाया गया है कि यह सबके हित के लिए पूछा जा रहा है तो उन्होंने बताने के लिए अनाकानी नहीं की इस तरह सर्वेक्षण और साक्षात्कार का कार्य पूरा हुआ है। इस पद्धति के अन्तर्गत अनुसंधानकर्त्ता क्षेत्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है वरन् वहाँ अपने से कुछ प्रतिशत इकाइयाँ चुन लेता है और उनका अध्ययन करता है निष्कर्ष निकाल कर उनको लागू करना है। हुजूर तहसील जिला–रीवा नगर में जल संसाधन में निवास के क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए मैंने निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया है। रीवा नगर में जल संसाधन में निवास करने वाले परिवारों की भौगोलिक अध्ययन की कुल जनसंख्या लगभग 100 है। मैने 100 को समस्त मानते हुये 50 व्यक्तियों की भौगोलिक अध्ययन आदर्श रूप से अध्ययन करने के लिए मैंने निदर्शन पद्धति चयन किया है। उनकी भौगोलिक अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है।

हुजूर तहसील जिला–रीवा नगर में जल संसाधन एवं भौगोलिक अध्ययन करने के लिए दैव निर्दशन विधि से ज्ञात किया। रीवा जिले के हुजूर तहसीलनगर में जल संसाधन एवं भौगोलिक अध्ययन को आदर्श के रूप में चुना जा सके जल संसाधन वालों की सभी व्यक्तियों की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति का प्रतिविध करने की बराबर सम्भावना बनी रहती है।

प्राथमिक समंकों के लिए मैं स्वयं हुजूर तहसील जिला–रीवा नगर में जल संसाधन एवं भौगोलिक अध्ययन के द्वारा प्रश्नों के उत्तर पूछकर अपनी अनुसूची में भरा तथा उनका साक्षात्कार भी किया साथ ही अवलोकन भी किया इसे प्राथमिक समंक इसलिए कहा जाता है। कि मैंने पहली बार जल संसाधन एवं भौगोलिक अध्ययन किया क्योंकि मैंने स्वंय उस क्षेत्र में जल संसाधन एवं भौगोलिक अध्ययन के विकास निरीक्षण किया और संबंधित लोगों से सम्पर्क करके पूछा जिस संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करना है। उनका भलीभाँत निरीक्षण करके वह व्यर्थ को छोड़कर उपयोगी समग्री को प्राप्त करने की कोशिश करना है।

जल संसाधन एवं भौगोलिक अध्ययन की संख्या एकत्रित किया उनके द्वारा प्रस्तुत की गई समग्री के ये मौलिक स्वरूप है। प्राचीन काल से ही भारत में पुराने तरीकों से कृषि कार्य होता चला आ रहा है। शायद इसका प्रमुख कारण है रहा होगा कि भारतीय शासन में लगातार परिवर्तन होता रहा, लम्बे समय तक स्थायी शासन न होने से ग्रामीण एवं कृषि विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये वैज्ञानिक कृषि के क्षेत्र में पश्चिमी देशों की अपेक्षा यहां अल्प विकास हुआ संभवतः इस दिश में पहला कदम 1860 के लगभग उठाने का श्रेय ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दिया जा सकता है जब उसने भारतीय किसाानों को कृषि कार्यों से अधिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल संसाधनों के विकास के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया और भारतीय किसानों को कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलों को पैदा करने का प्रयास किया।

18वीं शताब्दी में देश में अनेक बार अकाल पड़ने के कारण सन् 1900 में अकाल आयोग की स्थापना की जिस जिसकी रिपोर्ट से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 1903 में पूसा (बिहार) में इपीरियल कृषि शोध संस्थान नामक संस्था खोली गयी। जिसे बाद में कतिपय कारणों से दिल्ली लाया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् रख दिया। 1926 में कृषि पर राजकीय आयोग की नियुक्ति होने के

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

पूर्व तक कृषि विकास को समन्वित और विस्तृत दृष्टिकोण से नहीं सोचा गया था। आयोग ने अपनी विशिष्टता के अनुसार उस समय देश में उन्नतशील बीज एवं कृषि में उपयोग होने वाले संसाधान के विकास की सिफारिश की। जिससे भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में कृषि की दशा का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट व सुझाव दिये इससे सरकार ने कृषि विकास की नीतियों में आवश्यक परिवर्तन और सुधार कर दिया। इस समय देश के किसानों की स्थिति बहुत बुरी थी अधिकांश किसान गरीब थे और साहूकारों द्वारा दिया गया ऋण उन पर लदा हुआ था। वे छोटे–छोटे खेतों में पुराने तरीके से खेती करते थे जिससे ज्यादा समय में कम कार्य एवं उत्पादन होता था। अच्छे बीज, उत्तम खाद, बढ़या किस्म के कृष उपकरणें, एवं सिंचाई के लिए प्रमुख रूप से जल संसाधनों आदि का अभाव था। जो कुछ आधुनिक एवं विकसित साधन उपलब्ध थे, गरीबी और जानकारी के अभाव में वह उनके प्रयोग से वंचित था। सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। प्रचलित भू–धारण प्रणालियां भी इस प्रकार की थी कि साधारणतया कास्तकारों के लिए कृषि विकास के कार्य में दिलचस्पी लेने एवं उसके लिए साधन जुटाना सम्भव न रह गया था।

भारत में समस्त भूतल जल तथा भूमिगत जल का स्रोत अन्ततः आन्तरिक वर्षा ही है। भूतल जल से अर्थ भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल से है। जो सामान्यतया नदियों, तालाबों तथा नहरों आदि में पाया जाता है। भूमिगत जल से तात्पर्य भूमि के नीचे पाये जाने वाले जल से है जिससे कुओं तथा ट्यूबबेलों के माध्यम से निकाल कर काम में लाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार वर्षा से देश में प्रति वर्ष लगभग 3,70,044 करोड़ घनमीटर जल प्राप्त होता है जिसमें से केवल 1,67,753 करोड़ घन मीटर जल नदियों में चला जाता है। शेष जल या तो भूमि सोख लेती है अथवा भाप बनकर उड़ जाता है। योजनाकाल में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि तथा बाढ़ नियन्त्रण हेतु भारी मात्रा में धनराशि व्यय की गई है जिसके फलस्वरूप देश में सिचाई की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। रीवा नगर में टोन्स या टमस बीहर ओड्डा व उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ उत्तर पूर्व की ओर बहकर गंगा नदी में मिलती है। ये नदियाँ सुन्दर व ऊँचे जल प्रपात बनाती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ बिछिया बीहर नदियाँ हैं, जो आगे चलकर घोघर नदी का रूप ले लेती है। कैमूर पहाड़ से सतना जिले के खरम खण्ड नामक स्थान से निकलती है तथा उत्तर पूर्व की ओर बहती है। रीवा नगर के पास बिछिया नदी भी इसमें मिल जाती है। बिछिया और बीहर मिलकर घोघर नदी बनाती हैं जो आगे चलकर टोन्स नदी में मिल जाती हैं। चचाई गाँव के पास चचाई सुन्दर प्रपात बनाती है। यह हुजूर तहसील के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। यह रीवा नगर के पास बीहर नदी में मिलकर घोघर नदी बनाती है। जो घोघर नदी के नाम से प्रसिद्ध है।

रीवा नगर की जलवायु का अध्ययन तीन वर्गो में वर्गीकृत किया गया है– नवम्बर से फरवरी तक शीतकाल, मार्च से जून तक ग्रीष्मकाल, 15 जून से अक्टूबर तक वर्षाकाल। हुजूर तहसील रीवा नगर का तापमान मई–जून में 47.77 पहुँच जाती है। इस महीने में भीषण गर्मी के कारण पानी की मात्रा में भी कमी हो जाती है। वायु अधिकांशतः पश्चिम दिशा की ओर चलती है, जबकि शरदऋतु दिसम्बर जनवरी के महीनों में रीवा नगर का तापमान शून्य डिग्री हो जाता है। और कड़ाकी ठण्डी पड़ने लगती है। हुजूर तहसील रीवा नगर की आर्थिक स्थिति पूर्व के दशकों में अत्यंत दयनीय थी, किन्तु देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ हुजूर तहसील रीवा नगर का भी विकास हुआ है। वर्तमान समय में हुजूर तहसील रीवा नगर आर्थिक प्रगति और निरंतर अग्रसर है। हुजूर तहसील रीवा नगर जिला में होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था पूर्णरूप से कृषि पर आधारित है। वर्तमान समय में कृषि का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, चना, सोयाबीन, असली सरसों, चावल, अरहर, उड़द, मूँग आदि है। रीवा जिले के हुजूर तहसीलनगर में औद्योगिक विकास के लिये भी कुछ योजनायें बनाई गई हैं। रीवा नगर में उद्योग का काफी विकास हुआ है। रीवा जिले के हुजूर तहसीलमें अधिकांश उद्योग लघु और कुटीर उद्योग है, यहाँ पर जे0पी0 सीमेंट फैक्ट्री एवं अनेक छोटे उद्योग भी है। रीवा नगर में मध्यम श्रेणी उद्योग काफी मात्रा में है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

हुजूर तहसील में जिला रीवा के अनेक तरह की संसाधन है जिसमें जिस प्रकार यहां दो मुख्य नहरों का निर्माण यिका है जिससे हुजूर तहीहसल अपर पुरवा सिंचाई की जाती है जिससे वर्तमान में लगभग 70 प्रतिशत की नहरों से सिंचाई की जाती है और क्योंटी कैनाल से भी सिंचाई की जा रही है यहां के किसान नहरों के विकास से ज्याद से ज्याद लाभ उठाया है। **रीवा जिले के हुजूर तहसील** एक कृषि प्रधान देश है। हुजूर तहसील की प्रमुख उपजों में गेहूँ, चावल, मक्का, चना, मटर, ज्वार, जौ आदि हैं। अरहर, उड़द, मूंग का उत्पादन साधारण होता है। देश में जल संसाधनों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित संस्थाओं का गठन किया गया है – यह जल संसाधनों के विकास के लिए गठित एक सर्वोच्च तकनीकी संस्था है जिसकी स्थापना 1995 में की गयी थी। इस आयोग का कार्य जल संसाधनों के उपयोग, संरक्षण तथा नियन्त्रण हेतु योजनाएं बनाना तथा उन योजनाओं में समन्वय स्थापित कर उनका विकास करना है। यह बाढ़ नियन्त्रण, सिंचाई तथा जहाजरानी के लिए राज्य सरकारों से विचार–विमर्श कर उन्हें सलाह देता है। बाढ़ नियंत्रण तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में आयोजन, अनुसंधान, रूपांकन, प्रबन्ध तथा मूल्यांकन के सम्बनध में आयोग महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

यह भूमिगत जल के सम्बन्ध में सर्वोच्च संस्था है। इस बोर्ड की स्थापना 1952 में की गयी थी परन्तु 1972 में भारत के भूगर्भ सर्वेक्षण की भूमिगत जल इकाई को इसके साथ मिलाकर इसका पुनर्गठन कर दिया गया। इस बोर्ड का कार्य भूमिगत जल के सम्बन्धा में सर्वेक्षण करना, सम्भावनाओं का पता लगाना, मूलयांकन करना तथा भूमिबत जल की गुणवत्ता व पद्धति की मानीटरिंग करना आदि है। यह बोर्ड पूरे देश में भूमिगत जल के विाकस के सम्बन्ध में नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम बनाता है। इस बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है तथा इसके दो सदस्य होते हैं। इसके 11 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 12 राज्य स्तरीय कार्यालय व 15 इंजीनियरिंग प्रखण्ड हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1982 में की गई। इसका कार्य नदियों के मिलाकर पानी के सदुपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाना है ताकि पानी को आधिक्य वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों मे पहुंचाया जा सके।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

चित्र क्रमांक 1 रीवा जिले के हुजूर तहसील के अन्तर्गत नहरों द्वारा सिंचाई से कृषि क्षेत्र में प्रगति के द्वार खुले

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के प्रतयक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 75 प्रतिशत लोग इसमें कार्यरत हैं भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। जिससे 75 प्रतिशत लोग जीवन निर्वाह करते हैं । भारत में कृषि उत्पादन ऐसी वस्तुओं का भी होता है जो विदेशी होती है नहीं या अल्प मात्र में होती है। यहां का मुख्य उत्पाद सोयाबीन, धान, तिलनहन, गेहूँ, जौ, चना, मसूर तथा अन्य कृषि उत्पाद यहां की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। यहां प्रमुख रूप से जल संसाधनों का पूर्व में अभाव होने के कारण आर्थिक दशा कम जोर थी। लेकिन आजादी की बाद यहां पर जल संसाधनों का विकास निरन्तर होता रहा जो वर्षा के पानी को रोंकने का कार्य की शुरूआत हुई जगह–जगह नदियों नालों में स्टाप डैम का निर्माण कराया जाने लगा और वर्षा के जल को रोंक कर कृषि में सिचाई के रूप में डीजल पम्प, विद्युत पम्प, कुआँ, तालाबों आदि से जल स्रोतों का विकास होने लगा और ज्यादा– से ज्यादा किसानों ने अपने स्वयं के जल संसाधनों का विकास करने का प्रयास किया। जिससे यहाँ की कृषि अर्थव्यवथा में नवीन तरीके से कृषि से उत्पन्न खाद्यान्नों की पैदावार में बढ़ोत्तरी होने लगी।

रीवा नगर हुजूर तहसील के अन्तर्गत आता है। हुजूर तहसील में प्रमुख रूप से जल संसाधनों में जैसे–बाणसागर परियोजना यहाँ की बहुउद्देशीय परियोजना है। जो केन्द्र सरकार के द्वारा 1977 में प्रोजेक्ट की गई थी। इस परियोजना की मुख्य कल्पना यमुना प्रसाद शास्त्री जी की थी जो आज बन संवर कर कार्य रूप में परिणित हो गई है। इस परियोजना में केन्द्र सरकार के साथ तीन राज्यों को भी शामिल किया गया है क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्यप्रदेश। इस परियोजना में तीनों राज्यों की जल की कमी को पूरा करने के लिए सरकार दृढ़ होकर परियोजना को साकार रूप दिया जो वर्तमान में बाणसागर परियोजना के नहरों का विकास होने से हूजुर तहसील में सिंचाई की क्षमता को करीब 70 प्रतिशत की पूर्ति होती है। इस परियोजना के विकसित होने के कारण यहां पर जल संसाधन का भरपूर उपयोग किसानों द्वारा किया जा रहा है। यह बाँध सोन नदी के ऊपर बनाया गया है। इस बांध के अन्तर्गत ब्यौहारी, अमरपाटन, रामनगर, रघुराजनगर, मैहर, कटनी आदि तहसीलें प्रभावित हुई हैं। जिसकी आबादी को पुनर्वास योजना के तहत उनके निवास स्थान को हटाकर अन्यत्र बसाया गया है। परियोजना का कार्य वर्तमान में भी युद्धस्तर पर निर्माण कार्य जारी है। इस

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

योजना के द्वारा प्रमुख रूप से ऊर्जा (बिजली) रूप में जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है जिससे देश एवं प्रदेश को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना के द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मत्स्य उद्योग में वृद्धि हुई है। इससे जिले के आय में वृद्धि हुई। जहां कृषि के क्षेत्र का प्रश्न है वहां पर नहरों के बुनियादी विकास होने के कारण हुजूर तहसील के किसानों को भरपूर जल की उपलब्धता हो रही है। इसके परिणामस्वरूप कृषिजन्य खाद्यान्नों का तेजी से उत्पादन बढ़ा है जिससे यहां के कृषिकों की आर्थिक दशा में विकास हुआ है। यहाँ के पिछड़ेपन की आर्थिक एवं सामाजिक स्तर बढ़ा है।

हुजूर तहसील के अन्तर्गत त्रिवेणी, कलरा, निमिहा, कपड़हाई धार, झिरिया, छिरहा, कुबरा के जलग्रहण क्षेत्र को एक प्राकृतिक इकाई मानते हुए भूमि को सतह के सबसे ऊंचाई वाले बिन्दु से लेकर जहां तक पूरे क्षेत्र का पानी बिछिया नदी में एकत्रित होता है उसे चिन्हांकित किया गया है। इसकी सीमा किसी भी इकाई (जैसे पंचायत ग्राम इत्यादि) की प्रशासकीय सीमा से सामान्यतः भिन्न होती है। योजना बनाने एवं लागू करने में सुलभता की दृष्टि से जलग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र में आने वाले समस्त भूमि एवं जल संसाधनों का विकास भू तथा नमी संरक्षण उपायों और जल एकत्रित करने के साधनों का निर्माण कर किया जाता है। इससे जहां एक ओर भू–क्षरण को रोककर मिट्टी में नमी तथा जल उपलब्धता की वृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर मिट्टी की उत्पादक क्षमता में गुणात्मक सुधार से कृषि पैदावार में भी सुधार परिलक्षित होता है। उपजाऊ मिट्टी तथा जल संसाधनों की बहुलता से उत्तम प्रकार की अधिक पैदावार वाली फसलों, नगदी फसलों, वानिकी व चारागाह विकास से प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि और पर्यावरण संतुलन कायम करने की दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के साथ–साथ रोजगार के अवसर बढ़ाकर स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया जा रहा है।

जल ग्रहण क्षेत्र पर आधारित एकीकृत योजना के अंतर्गत न केवल भूमि एवं जल प्रबंधन के कार्य सम्पादित किया जाना है। परन्तु तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त भूमि उपयोग, फसल चक्र उद्यानिकी वानिकी एवं चारागाह विकास पर आधारित पशुपालन, डेयरी, रेशम उद्योग एवं कुटीर उद्योगों द्वारा स्थानीय लोगों को आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव हैं।

उपरोक्तानुसार जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विकास पर पर्यावरण में संतुलन कायम करना तथा विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्राकृति, संसाधनों, भूमि उपयोग तथा जल निकास की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर उनमें संरक्षण, संवर्धन व विकास के विकल्पों का पता लगाकर क्षेत्र का पता लगाकर क्षेत्र मे निवास करने वाले स्थानीय लोगों की सहायता से उनको लागू करना है। इसमे जहां तक संभव हो सकें स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों तथा लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकी का उपयोग किये जाने का प्रयास होना चाहिए। ताकि निर्मित संसाधनों के रख–रखाव तथा स्थानीय विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है।

इस प्रकार से निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार के सम्मिलित प्रयासों से बाणसागर बहुउद्देश्यी परियोजना का विकास होने से पूरे हुजूर तहसील के अन्तर्गत आने वाले कृषिकों के जीवन में खुशहाली आयी है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, साथ ही रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

संदर्भः

[1]. गुरुरामप्यारे अग्निहोत्री ''रीवा राज्य का इतिहास''

[2]. प्रो. राधेशरण – विन्ध्य क्षेत्र का इतिहास (वृहत्तर–बघेलखण्ड) मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, प्रथम संस्करण –2001

[3]. सिंह जीतन – रीवा राज्य दर्पण

[4]. प्रत्यक्ष अवलोकन एवं पुरातत्व अभिलेखागार के अधिकारियों से बातचीत के आधार पर।

[5]. भू–अर्जन एवं पुनर्वास संभाग, बाणसागर परियोजना, रीवा (म.प्र.) वर्ष 2019 प्राप्त आंकडे